# Prabhat Khabar's Senior Journalist Rajeev Pandey Received 'Laadli Media Award' | Jharkhand | 25 Oct 2023

## Why In News?

Recently, Rajiv Pandey, a senior journalist of Prabhat Khabar's Ranchi unit, has been awarded the 'Laadli Media Awards 2023' by 'Population First', a prestigious organization working in the field of gender equality.

## Key Points:

- The Laadli Media Award is given by the 'Population First' organization for promoting gender sensitivity. The Laadli media award was announced by the organization on October 21 this year.
- More than 850 journalists from across the country in 13 languages had submitted entries for the award, out of which 87 were selected and felicitated by the jury members. Apart from these, 31 journalists were given jury commendation letters.
- Prabhat Khabar has received the award at the 13th Laadli Media and Advertising Award for Gender Sensitivity (Regional) 2023 organized by Population First Organization. Last year, another journalist of Prabhat Khabar, Guruswaroop Mishra, was also honoured with the award.
- He received the award for a story on domestic workers titled 'Poor condition of domestic workers, no leave and no proper wages' published by Rajiv Pandey, chief correspondent of Prabhat Khabar Ranchi unit.
- The vice-chancellor of Baba Amte Divyang University, Jaipur, Prof. S.K. Singh was also present on the occasion. Dr Dev Swarup, Head of Policy and Partnerships, United Nations Population Fund, Jaideep Biswas, Programme Management Specialist, UNFPA, Anuja Gulati, Programme Management Specialist and Kalyan Singh Kothari, Secretary, Lok Samvad Sansthan felicitated Pandey.
- It is worth mentioning that Rajiv Pandey has already been given three fellowship awards by Chennai-based institute REACH. In the year 2014, jharkhand has received fellowships on the status of TB disease, non-communicable diseases in the year 2019 and diabetes in the year 2023.

//

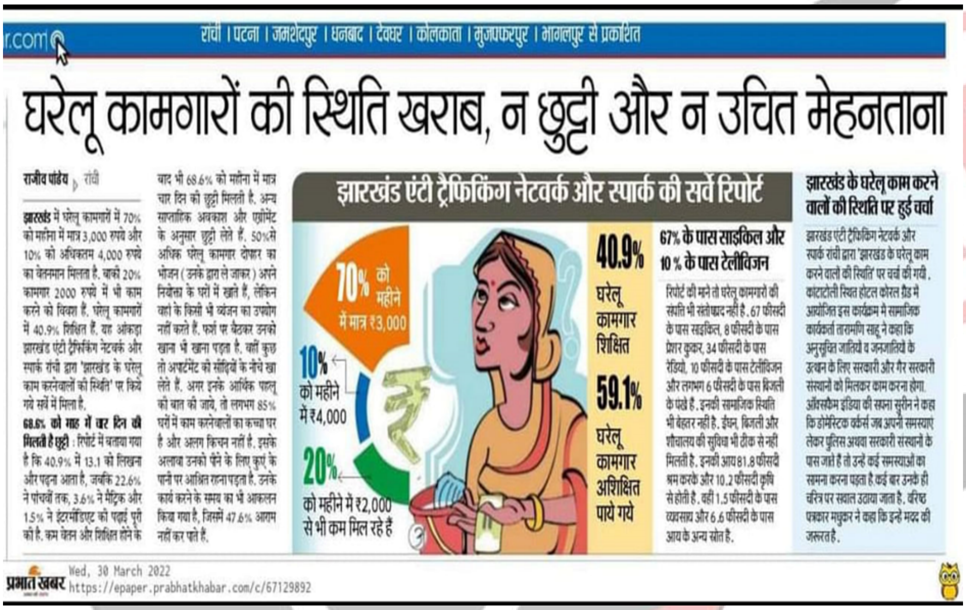

r.com | रांची | पटना | जमशेदपुर | धनबाद | देवघर | कोलकाता | मुजफ्फरपुर | भागलपुर से प्रकाशित

# घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी और न उचित मेहनताना

**राजीव पांडेय** रांची

**झारखंड** में घरेलू कामगारों में 70% को महीना में मात्र 3,000 रुपये और 10% को अधिकतम 4,000 रुपये का वेतनमान मिलता है. बाकी 20% कामगार 2000 रुपये में भी काम करने को विवश हैं. घरेलू कामगारों में 40.9% शिक्षित हैं. यह आंकड़ा झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करनेवालों की स्थिति' पर किये गये सर्वे में मिला है.

**68.6% को माह में चार दिन की मिलती है छुट्टी** : रिपोर्ट में बताया गया है कि 40.9% में 13.1 को लिखना और पढ़ना आता है, जबकि 22.6% ने पांचवीं तक, 3.6% ने मैट्रिक और 1.5% ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है. कम वेतन और शिक्षित होने के बाद भी 68.6% को महीना में मात्र चार दिन की छुट्टी मिलती है. अन्य साप्ताहिक अवकाश और एग्रीमेंट के अनुसार छुट्टी लेते हैं. 50%से अधिक घरेलू कामगार दोपहर का भोजन (उनके द्वारा ले जाकर) अपने नियोक्ता के घरों में खाते हैं, लेकिन वहां के किसी भी व्यंजन का उपयोग नहीं करते हैं. फर्श पर बैठकर उनको खाना भी खाना पड़ता है. वहीं कुछ तो अपार्टमेंट की सीढ़ियों के नीचे खा लेते हैं. अगर इनके आर्थिक पहलू की बात की जाये, तो लगभग 85% घरों में काम करनेवालों का कच्चा घर है और अलग किचन नहीं है. इसके अलावा उनको पीने के लिए कुएं के पानी पर आश्रित रहना पड़ता है. उनके कार्य करने के समय का भी आकलन किया गया है, जिसमें 47.6% आराम नहीं कर पाते हैं.

## झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क की सर्वे रिपोर्ट



### 67% के पास साइकिल और 10 % के पास टेलीविजन

रिपोर्ट की मानें तो घरेलू कामगारों की संपत्ति भी संतोषप्रद नहीं है. 67 फीसदी के पास साइकिल, 8 फीसदी के पास प्रेशर कुकर, 34 फीसदी के पास रेडियो, 10 फीसदी के पास टेलीविजन और लगभग 6 फीसदी के पास बिजली के पंखे हैं. इनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर नहीं है. ईंधन, बिजली और शौचालय की सुविधा भी ठीक से नहीं मिलती है. इनकी आय 81.8 फीसदी श्रम करके और 10.2 फीसदी कृषि से होती है. वहीं 1.5 फीसदी के पास व्यवसाय और 6.6 फीसदी के पास आय के अन्य स्रोत है.

### झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर हुई चर्चा

झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्पार्क रांची द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति' पर चर्चा की गयी. कांटाटोली स्थित होटल कोरल ग्रैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि साहू ने कहा कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्थान के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा. ऑक्सफैम इंडिया की सपना सुरीन ने कहा कि डोमेस्टिक वर्कर्स जब अपनी समस्याएं लेकर पुलिस अथवा सरकारी संस्थानों के पास जाते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार उनके ही चरित्र पर सवाल उठाया जाता है. वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने कहा कि इन्हें मदद की जरूरत है.

प्रभात खबर Wed, 30 March 2022 https://epaper.prabhatkhabar.com/c/67129892


The Vision